

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
31/7/25 -	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादा परिष्कारादी उपास्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग ऑफिस मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत् दि. 24/9/2025</p>	
24/10/25	<p>पत्रावली पेश हो वकील पत्रावली उपा. अधीनस्थ अधिकारी के अधीनस्थ 1 व 2 की ओर से पत्रावली पत्र पेश किया, वकील पत्रावली हो मिसल वानि वदम के फाइलिंग 21/11/25 को पेश हो</p>	
21/11/25	<p>पत्रावली पेश हो वकील पत्रावली उपा. वदम सुनी गई मिसल वानि आदेश में पत्रावली दिनांक 5/12/25 को पेश हो</p>	
05/12/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमपपदा उपस्थित। पत्रावली के उमपपदा वदम सुनी गई थी विगत तारीख पेशी पर। अतः आज पत्रावली के प्राचीन पत्र वदम अधिवक्ता निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान कारखाने अधिनियम 1955 पर फैसला सुनाया गया। प्राचीन पत्र खामिज किया गया। उमपपदा वदम के जो कि विगत तारीख पेशी पर हुई थी उन विवेक से कोर्टोका है आजादी पूर्व पर वर्णित करते हुए मीनोबिंदु प्रथम दृष्टया मामला, अप्रुथीय क्षति व सुविध्य संकलन के</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डा. आर. पी. निगीत बिना गमा / सामही लोडिंग
 जी ध्यान रखा गया / निर्णय इस प्रकार है —
 उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन
 किया कि 03.07.2023 को प्रा०पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा
 गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख०नं० 47 रकबा 0.52 है०
 तथा 47/1364 रकबा 0.45 है० है। अप्रार्थी द्वारा पक्के रास्ते
 डामरीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है जो कि ग्राम
 पीपल्दा खुर्द से ग्राम नलावता की झोपडिया जाने वाले आम
 रास्ते की भूमि पर बनाया जाना है। प्रार्थी की कब्जे काश्त
 की भूमि में भी यह कार्य हेतु साफ-सफाई शुरू कर दी है।
 अप्रार्थी द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये प्रार्थी की आराजी पर
 सडक निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो कि
 अविधिक है क्योंकि प्रार्थीगण की आराजी को बिना अवाप्ति
 के सडक निर्माण में उपयोग में लिया जा रहा है। अगर
 सडक निर्माण प्रार्थी की भूमि में होगा तो प्रार्थी को अपूर्णीय
 क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
 की जावे। अप्रार्थी ने जवाब दिया कि रास्ता कच्चा रास्ता है
 जिसे वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा था जिसको ग्रामवासी
 नलावता की झोपडिया वाली मांग पर प्रचलित रास्ते का
 डामरीकरण कर दिया गया तथा डामरीकरण के दौरान किसी
 भी निजी भूमि का उपयोग नहीं किया गया तथा रास्ता प्रार्थी
 के खेत के पास स्थित सरकारी रास्ते पर किया गया।
 उभयपक्ष पर बहस पर मनन किया गया। चूंकि सडक निर्माण
 कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रा० पत्र के दर्ज कराने
 के उपरांत प्रार्थी द्वारा अर्जेंट नेजर का हवाला देते हुए कभी
 त्वरित सुनवाई का आग्रह भी नहीं किया। सडक निर्माण
 यदि सरकारी भूमि पर होता तो यह आमजन के हित में
 कनेक्टिविटी में सुधार हेतु उपयोगी मूलभूत आवश्यकता व
 इन्फ्रास्ट्रक्चर है। प्रार्थी अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को प्रमाणित
 करने में असफल रहा। इसलिए प्रा० पत्र बाबत अस्थाई
 निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
 जाकर दाखिल दफतर हो।

